

आईआईटी भवन के लिए मंजूरी का प्रस्ताव दिल्ली गया

इंदौर आईआईटी के स्थायी भवन निर्माण में हो रही देरी को लेकर प्रशासन ने जमीन की कमी दूर करने के साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी कवायद शुरू कर दी है। वन विभाग ने आपत्तियों को निराकृत कर प्रतिवेदन केंद्रीय मंत्रालय को भेज दिया है। डीएफओ मोहम्मद सईद ने बताया उम्मीद है कि एक महीने में मंजूरी आ जाएगी। आईआईटी को भी पर्यावरण मंत्रालय से मंजूरी लेने के लिए उनके स्तर पर प्रक्रिया के लिए कह दिया गया है। संभागायुक्त संजय दुबे का कहना है आईआईटी को आवंटित जमीन में आ रही कमी को एक सप्ताह में दूर कर लिया जाएगा, साथ ही फॉरेस्ट क्लियरेंस व अन्य मुद्दों को भी जल्द सुलझा लिया जाएगा।